सोसायटियों के प्रयोग का प्रश्न राज्य सरकारों के परामर्श से विचाराधीन है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य	गठित की गई कृषक सेवा सोसायटियों की संख्या	गठित की गई वृहत्-कार बहु-उद्देश्यीय सोसायटियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	31	—
2.	असम	—	—
3.	बिहार	5	32
4.	गुजरात	33	—
5.	हरियाणा	6	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1	—
8.	कर्नाटक	214*	—
9.	केरल	9	—
10.	मध्य प्रदेश	84	689
11.	महाराष्ट्र	18	38
12.	मणिपुर	2	—
13.	मेघालय	—	—
14.	नागालैण्ड	2	—
15.	उड़ीसा	1	44
16.	पंजाब	—	—
17.	राजस्थान	6	—
18.	तमिलनाडु	12	—
19.	त्रिपुरा	1	—
20.	उत्तर प्रदेश	51	—
21.	पश्चिम बंगाल	37	24
22.	गोवा, दमन तथा दीव	2	—
23.	पांडिचेरी	1	—
24.	दिल्ली	4	—
25.	अन्य केन्द्रशासित क्षेत्र	—	—
		520	827

*114 कोशकीटपालन कृषक सेवा सहकारी सोसाइटियों सहित।

सहकारिता बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज

4669. **श्री मनोहर लाल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारिता बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज में कमी करने का है जैसा कि बचत बैंक खातों पर ब्याज के मामले में किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख). सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों/अग्रिमों की ब्याज दरों को सामान्यतया कम करने का इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।